

घुसपैठियों पर भारत की नक्फ़ल, जीरो लाइन पर फ़ंसे 13 लोग; सैन्य धमकी पर उत्तरा बांग्लादेश

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत औं बांगलादेश के बीच अवैध प्रवासियों का लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गय है। अवैध बांगलादेशी घुसपैठियों को बापस भेजने की कोशिश को लेकर बांगलादेश का सरकार और सेना ने कड़ा विरोध जताया है। बांगलादेश के नेताओं ने इसे संप्रभुत पर हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भारत ने 67 बांगलादेशी को बापस भेजा, जबकि बुधवार को 12 लोग भारत-बांगलादेश सीमा की जी लाइन पर फँसे रहे। 26 मई को बांगलादेश सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था विभारत द्वारा अवैध लोगों को सीमा पार भेजना अस्वीकार्य है और जरूरत पड़ने पर सेना कार्रवाई के लिए तैयार है।

800 से ज्यादा लोगों को धकेलने का आरोप : इंडिया टुडे की रिपोर्ट वेबसाइट मुताबिक, अब तक करोब 100 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपा गया है। वहीं, बांग्लादेशी अखबार न्यूज एज ने दावा किया है कि 7 मई से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को भारत द्वारा बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की गई है। इनमें कथित भारतीय नागरिक और रोहिया शरणार्थी भी शामिल हैं। बुधवार को यूनाइटेड न्यूज बांग्लादेश एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि ब्रह्मगंगे स्थानीय लोगों की मदद से लालमोनिरहाट जिले के छह सीमा बिंदुओं से 57 लोगों को घुसने से रोक दिया।

A photograph showing four Indian paramilitary soldiers in camouflage uniforms and helmets standing in a row. They are holding rifles and looking towards the right. The background shows a dry, open landscape under a clear sky.

लालमोनिरहाट जीरो लाइन पर फंसे महिलाएं और बच्चे : द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, लालमोनिरहाट में जीरो लाइन पर 13 लोग न तो बांग्लादेश में घुस पा रहे हैं और न ही भारत में वापसी की उम्मीद रखते हैं। ये लोगों की वापसी बांग्लादेश संबंधों में तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री रोख हसीना को कुर्सी छोड़कर भारतीय भागना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश राजनीति में भारत-विरोधी तत्व मजबूत हो गया है।

का अनुमति मिल रहा हा इसमाहलाएँ और छोटे बच्चे भी हैं। छक्क अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने छक्क की ओर से अवैध रूप से लोगों को भेजे जाने की जानकारी मिलने पर भौंके पर पहुंच कर विरोध दर्ज किया। छक्क के बटालियन कमांडर अब्दुस सलाम ने बताया कि छक्क के साथ पलैंग मीटिंग का अनुरोध किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लालमोनिहाट के इस पार, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला स्थित है। यह क्षेत्र भारत-बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा है।

बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बल : यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत-

Digitized by srujanika@gmail.com

चैनलों के माध्यम से वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने भारत द्वारा अवैध प्रवासियों को धकेलने की प्रक्रिया को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। बांग्लादेश के सैन्य संचालन निदेशालय के निदेशक बिगोड़ियर जनरल मोहम्मद नजीम-उद-दौला ने भी कहा कि इनका इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत प्रभावी ढंग से संभाल रहा है। उन्होंने भारत के पुश-इन को अस्वीकार्य बताया और कहा कि यदि सरकार के निर्देश मिले, तो सेना हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। बीजीबी का फेसिंग पर भी विरोध भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 3,232 किलोमीटर को भारत सरकार ने फरवरी तक फेंस कर लिया है। लेकिन कई हिस्से अब भी असुरक्षित और विवादित हैं। बीजीबी ने पहले भी द्वारा बॉर्डर फेसिंग की कोशिशों का विरोध किया है। जनवरी में फेसिंग को लेकर दोनों देशों की बॉर्डर फोर्स के बीच तनाव देखा गया था। भारतीय गृह मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार, 2016 में देश में करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे थे, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेशी थे। हाल के वर्षों में राजस्थान, गुजरात और असम जैसे राज्यों में इनकी धरपकड़ तेज झुई है। खासतौर पर असम और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या परिवर्तन और हाल की मुश्शिदाबाद हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों की भूमिका की जांच हो रही है।

किसानों की बात नहीं सुनने पर ९
इंजीनियरों पर ऐकशन, प्रतिकूल
प्रविष्टि दी, प्रमोशन भी रोका

लखनउ, एजेंसी। किसानों की समस्याओं के निदान में लापरवाही करने, उनके धरना स्थल पर न पहुंचने, सीएम आवास जा रहे किसानों से बाती न करना आवास विकास के नी इंजीनियरों को भारी पड़ गया है। नी इंजीनियरों के खिलाफ योगी सरकार ने ऐक्षण लिया है। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने मामले में आवास विकास के इन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया है। एक अधिसारी अधियंता, तीन सहायक अधियंता तथा पांच अबर अधियन्ता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। अब इन इंजीनियरों का प्रमोशन रोक दिया गया है। उनकी सेवा के दौरान आगे इन इंजीनियरों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। ऐक्षण के बाद विभाग में हड्डकंप मच गया है।

आवास विकास परिषद की अवधि विहार योजना के किसान 23 अक्टूबर 2024 को योजना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आवास विकास का कोई इंजीनियर इन किसानों के बीच नहीं पहुंचा। किसानों की समस्याओं के निदान का प्रयास नहीं किया। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने सीएम आवास की तरफ बूँच कर दिया था। तब भी इंजीनियर इनसे बार्ता करने नहीं गए। जिससे असहज स्थिति पैदा हुई। किसान आवास विकास मृष्णालय भी आए थे। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने इस मामले में जांच बैर्टाइ थी। जोनल आवास आयुक्त हिमाशु गुरा ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट आवास आयुक्त के पास भेजी थी। अब इस मामले में आवास आयुक्त ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आवास आयुक्त ने जांच में जिम्मेदार व दोषी पाए गए नौ इंजीनियरों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इससे अब इन इंजीनियरों का उनकी सेवा के दौरान आगे प्रमोशन नहीं हो पाएगा। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने अधिशासी अधिवनता शासक पाण्डेय, सहायक अधिवनता प्रमोद कुमार, शुभम सिंह, राकेश कुमार तथा अबर अधिवनता कुंदन कुमार, मनुदेव, आनन्द भवन सिंह, पवन कुमार व विमल कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। आवास विकास के प्रदेश की अन्य योजनाओं में घटिया निर्माण करने वाले कई और इंजीनियर आवास आयुक्त के निशाने पर हैं। इन इंजीनियरों के खिलाफ भी जल्दी ही कार्रवाई होगी।

कनाटक में मार्गिद के सचिव की हत्या, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिए जांच के आदेश

बंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में मंगलवार को जुमा मस्जिद के अब्दुल रहमान की हत्या के बाद तनाव बढ़ दुआ है। सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को हिस्सा में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने और जाच करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें 32 साल के अब्दुल रहमान की हत्या 27 मई को कर दी गई थी। पुलिस द्वारा दज एफआईआर के मुताबिक रहमान और उनके साथी कलंदर शफी दोपहर करीब 3 बजे ट्रक से रेत उतार रहे थे। उसी वक्त उनके ऊपर करीब 15 लोगों के एक समूह ने हमला दिया। तलवार, चाकू और गोड़ लिए इन लोगों ने रहमान और शफी के ऊपर जानलेवा हमला किया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा मैंने पुलिस को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया है, जिससे पत चले की इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था। पुलिस एफआईआर में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें दो के नाम दीपक और सुमित्र हैं। इस हमले में घायल शफी ने बताया कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया वह हमारे जानेवाले ही थे। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले निसार ने बताया कि हम लोग रेत उतार रहे थे, तभी वह लोग आए और उन्होंने रहमान को ड्राइवर सीट से खींच लिया।

भारत-पाक विवाद पर पोस्ट करने वाली छांग्रा को राहत

दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल में बंद 19 वर्षीय छात्रा को जमानत देते हुए महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। छात्रा को भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में एक ऑनलाइन पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे के एक कॉलेज से निष्कासित और ऑपरेशन सिंट्र के दौरान भारत-पाकिस्तान विवाद पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के कारण 9 मई से जेल में बंद 19 वर्षीय छात्रा की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। उसने छात्रा की गिरफ्तारी को बेहद चौकाने वाला बताया और मौखिक रूप से कहा कि राज्य की ओर से इस तरह की कटूपंथी प्रतिक्रिया लोगों को कटूपंथी बना देगी। छात्रा को मंगलवार देर रात व्यवदा जेल से रिहा कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरीशी पर टिप्पणी के दो मामले, दो नजरिक्या है मामला छात्रा पुणे के सिंहागढ़ अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग में बोटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। छात्रा को 9 मई को निष्कासित कर दिया था, जब उसके खिलाफ पुणे के कॉलेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अपनी याचिका में छात्रा ने दाव किया कि उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना या सुनवाई का कोई मौका दिए बिना मनमाने तरीके से निष्कासित कर दिया गया और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ सर्वधान बेरहमी अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने बिना किसी गलत इरादे के इंस्टाग्राम पोस्ट को केवल दोबार पोस्ट किया था और तुरंत माफी भर्ती मांग ली थी। छात्रा के इस पोस्ट के



गर्मी की छुट्टियों में फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को नहीं मिलेगा आराम

फरीदाबाद, एजेंसी। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के टीचर गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर-घर जाकर माता-पिता के अपने बच्चों के दाखिले के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सभी टीचर्स को हर दिन 10 माता-पिता से संपर्क करना होगा और उन्हें हरियाणा सरकार के स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा और सरकारी स्कूलों की उपलब्धियां बतानी होंगी।

और प्राथमिक कक्षा में होती है। अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने नहीं आते हैं। शिक्षा निदेशालय के यह आदेश सभी जिलों के लिए आवश्यक है। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी होगी। टीचर्स ने किस क्षेत्र में सर्वे किया, कितने पैरेंट्स से मिले और उनके मोबाइल नंबर आदि डिटेल एक सीट में दर्ज करनी होगी। इसके अलावा उसमें कितने बच्चों के दाखिले में सफल रहे, इसकी भी जानकारी देनी होगी। दाखिले कम होने का यह भी है एक कारण फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है। यहां की कॉलोनियों में किराये का मकान लेकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। अधिकतर लोग ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं ठेकेदार का काम खत्म होने पर मजदूर अपने बच्चों के साथ नई साइट पर चल जाते हैं। इसके चलते वह अपने बच्चों का दाखिला नहीं करते हैं। यह भी एक कारण है कि फरीदाबाद में दाखिलों की संख्या कम रहती है। महेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, बल्लभागढ़, टीचर्स को शिक्षा निदेशालय के निर्देश से अवगत करा दिया गया है। यह सभी स्कूलों के टीचर्स के लिए आवश्यक है। इसकी

सप्ताह में छह दिन कर पाएंगे सोमनाथ की यात्रा, नई वटे भारत सफर में देगी साथ



एकजीक्यूटिव चेयर कार के विकल्प मौजूद हैं, जिसमें आरामदायक सीटिंग, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली, ऑटोमेटिक दरवाजे और बेहतर सफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस ट्रेन की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में बने भारत के पहले 9000 हॉर्सपावर वाले डी-90 इलेक्ट्रिक इंजन का भी उद्घाटन किया, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इस ट्रेन के माध्यम से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को रफ्तार मिलेगी बल्कि गुजरात के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नया आयाम मिलेगा। सावरमती-वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से सोमनाथ जैसे पवित्र स्थल की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और अधिकाधारक हो जाएगी।

ਮੇਰੀ ਪਲੀ ਨੇ ਏਕ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸ਼ਤਾਨ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਿਯਾ, ਮੈਂ ਭੀ ਗਿਆ ਥਾ: ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਾਂਸਦ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। असम सीएम एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले काफी समय से कांग्रेस नेता गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' से कथित संबंध को लेकर हमला कर रही है। अब पहली बार गौरव गोगोई ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने असम सीएम के दाव को किसी सी-येड बॉलीवुड मूवी का प्लॉट करार दिया है।

कहा कि उनकी पत्नी ने 2013 में केवल एक साल के लिए दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना के तहत पाकिस्तान में काम किया था। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी एक जानी-मानी पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ है। लगभग 14-15 साल पहले वह दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय पहल का हिस्सा थीं। इसके तहत उन्होंने एक साल पाकिस्तान में बिताया और फिर 2012-13 में भारत आ गई, जहां वह तब से काम कर रही हैं। 2015 में

गौरव गोगोई का पक्ष: गोगोई ने बुधवार को इस मामले पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एक नई नौकरी शुरू की। गोगोई ने आगे कहा कि वह 2013 में अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस यात्रा को सी-प्रेड बॉलीबुड मूँबी की तरह पेश कर रहे हैं, जिसका रिलीज डेट 10 सितंबर कहा जा रहा है।

ही सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान की नजर में उनकी छवि खराब करने के मकसद से कथित पाकिस्तानी संबंध को लेकर अरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्हें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से मुख्यमंत्री के मंसूबे विफल हो गए। कांग्रेस ने गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी है, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा एवं भाजपा उनकी पली के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' से कथित संबंध तथा कांग्रेस सांसद के पाकिस्तान दौरे को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। मेरे कद को बहुत ऊँचा कर दिया- गोगोई का तीखा हमला आरोपों को खारिज करते हुए गोगोई ने पिछ्ले दिनों मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था। गोगोई ने बुधवार को शर्मा पर कटाश करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री का तहसिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाजपा नेता ने उनके राजनीतिक कद बढ़ाने में मदद की। उन्होंने कहा, “पहले परिसीमन में सिर्फ मेरे लोकसभा क्षेत्र (कलियाबोर) के दो टुकड़े किए, पिर मुख्यमंत्री कुछ महीने से जिस तरह की बौकी बातें कर रहे हैं, उसने मेरे कद को बहुत ऊँचा कर दिया है। पहले एक भ्रम था कि मेरी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित है।

